(घ) पूरे देश में जमाखोरी-विरोधी अभियान को लागू करने के लिए सरकार द्वारा उपाय किये जाने का प्रस्ताव हैं।

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) प्रधानमंत्री समय-समय पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कुशल कार्यान्वयन और यह सुनिश्चित करने पर कि आपूर्ति उपभोक्ताओं तक बहुत बल देते हैं।

(ख) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु प्रचालनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की हैं। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की हैं। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी में लगे और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबंधों तथा उसके तहत जारी नियंत्रण आदेशों का अन्य प्रकार से उल्लंघन करने वाले बेईमानन तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन और आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रवर्तन की राज्य सरकारों के साथ समय-समय पर समीक्षा की जाती है । केंद्रीय सरकार को ऐसी सूचना नहीं मिली है कि राज्य सरकारें आवश्यक वस्तु अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में केंद्रीय सरकार की सलाह का अनुसरण नहीं कर रही है। राज्य सरकारें आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई की सूचना केंद्रीय सरकार को आवधिक रूप से दे रही है।

कंद्रीय सरकार के पास आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन हेतु अलग से कोइर् तंत्र नहीं है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभागों के अधिकारी और कर्मचारी आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों और उसके तहत जारी नियंत्रण आदेशों को लागू करने के अपने कार्य के एक हिस्से के रूप में, निरीक्षण करते हैं और छापे मारते हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह सलाह दी गई है कि जब कभी भी यह महसूस किया जाए कि बेईमान तत्वों द्वारा सट्टेबाजी के लिए की गई जमाखोरी के कारण किसी आवश्यक वस्तु की उपलब्धता और मूल्यों पर प्रतिकृल प्रभाव पड़ा है तो वे जमाखोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाएं।

केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र

5 शासनों को इस संबंध में पत्रों और बैठकों में माध्यम से समय-समय पर सलाह देती हैं।

Cost of elimination of child labour

- 689. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:
- (a) whether it is a fact that according to Government's estimates the cost of elimination of child labour comes to Rs. 12,720 per child;
- (b) whether it is also a fact that International Labour Organisation has estimated the cost of elimination of child labour at Rs. 1,390'—; and
 - (c) if so, the reasons for the difference?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) and (b) No, Sir.

(c) Does not arise in view of reply to (a) and (b) above.

News-item regarding rising prices of pulses

690. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: SHRIMATI VEENA VERMA: SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleaesd to state:

- (a) whether Government's attention has been drawn to the report in the 'Statesman' of 23rd August, 1995 captioned, "price soar-buyers sore" regarding sky-packing prices of pulses, in the main commercial markets and in retail markets in the country; and
- (b) if so, the comparative prices of each type of pulses and dais in January, April and September, 1995?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (DEPTT. OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM) (SHRI

57

Items!

VENOD SHARMA): (a) and (b) Yes, Sir. A statement showing the comparative wholesale and retail prices of different types of pulses for January, April and September, 1995 is given below.

Statement

Month-end wholesale and Retail prices of Pulses at selected centres.

Wholesale Prices

(Rs. per Qtl)

Items'	Wholesale Prices						
Centre							
	Jan. '95	April ^95	Sept.				
GRAM							
Delhi Bombay Calcutta Madras ARHAR	1250 1800 1350 1420	980 1225 1130 1221	880 1225 950 1107				
Delhi	1450	1750	2300				
Bombay Calcutta Madras MOONG	1701 1350 2000	2075 2000 2530	2300 2350 2520				
Delhi	1570	1570	1675				
Bombay Calcutta MASUR	1400 NR	1500 NR	1600 NR				
Delhi	1500	1500	1600				
Bombay Calcutta URAD	1500 1480	1200 1400	1600 1750				
Delhi	1870	2450	2150				
Bombay Calcutta GRAM	1850 NR	1600 NR	2100 2700				
Delhi	15.00	13.00	14.00				
Bombay Calcutta Madras ARHAR	19.00 16.00 16.00	15.00 16.00 13.00	13.00 14.00 12.50				
Delhi	18.00	19.00	31.00				
Bombay Calcutta	18.00 19.00	23.00 21.00	28.00 27.00				
Madras	22.00	28.00	28.00				

		(Rs. per Qtl)				
Items'		Wholesale Prices				
Centre						
		Jan.	95	April ,95	Sept 95	
MOONG						
Delhi		22.	00	24.00	23.00	
Bombay		22.	00	23.00	23.60	
Calcutta		22.	00	22.00	24.00	
MASUR						
Delhi		19.	00	19.00	20.00	
Bombay		19.	00	18.00	19.00	
Calcutta		19.	00	20.00	23.00	
URAO						
Delhi		30.	00	36.00	36.00	
Bombay		30.	00	38.00	32.00	
Calcutta		23.	00	24.00	27.00	
SOURCE:	(i)	State G	ovt	s. Civil		

to Questions

Supplies Departments, (ii) Dts. of Economics & Statistics, Ministry of Agriculture.

NR: Note Reported.

Financial Assistance to Super Bazar

- 691. SHRI **GOPALSINH** SOLANKI: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER **AFFAIRS** AND **PUBLIC** DISTRIBUTION be pleased to state:
- (a) whether it is a fact that optimum utilization of funds is not being made in the Super Bazar;
- (b) if not, the amounts obtained as financial assistance in the Super Bazar during the last three years separately from all Government and public sources;
- (c) the amount out of the above financial assistance received and left unutilised at the end of each of the above said years; and
- (d) the percentage of the unutilised amounts for each year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (DEPTT.